समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 47 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

सी.ए.ए. विरोध के पीछे घातक मंसूबे – डॉ. किशन कछवाहा

भारत के संविधान की धारा 256 और 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य केन्द्र द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिये बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो केन्द्र सरकार उसे दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है।

इस तरह देश की तीन–चार विधान सभाओं द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध पारित किये गये प्रस्ताव असंवैधानिक, संघीय ढांचे के विरूद्ध तथा संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं।

संविधान की धारा –11(ग्यारह) कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को देती है। विधानसभाओं द्वारा पारित किये गये ऐसे प्रस्ताव केन्द्र सरकार और संसद के अधिकारों को छीनने का प्रयास है जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता।

जैसा कि अब तक सभी लोग भली–भाँति जान चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आये उन हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि को भारत की नागरिकता देने के लिये बनाया गया है जिन पर वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा वर्षों से जुल्म, अत्याचार के साथ–साथ तरह–तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। देश के दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे के बाद ये लोग किसी न किसी वजह से भारत नहीं आ पाये थे। नरेन्द्र मोदी सरकार ने उस विभाजन की ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुये ऐसे प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने में कतिपय राहत दी है जिनका काँग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल अंध विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री केप्टन अमरिन्दर सिंह ने भी इसके विरोध में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया है, जबकि उनकी माँ मोहिन्दर कौर ने सन् 1947 में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को तरह–तरह की मदद की थी। अब उनका यह बेटा शरणार्थियों के खिलाफ खड़ा होकर कांग्रेस के सामने घुटना टेक रहा है। आज भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं आदि के साथ घृणित किस्म के अत्याचार हो रहे हैं, वहां बहिन–बेटियाँ असुरक्षित हैं। तथाकथित नेताओं और शांतिप्रिय कहे जाने वाले मुस्लिमों की जबान से उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता।

इस कानून के विरोध के नाम पर सीरिया से लेकर शाहीनबाग तक एक ही मानसिकता मुस्लिम कट्टरवादिता काम करती नजर आ रही है। जन विरोध के नाम पर देश को अस्थिर बनाने वालों की असली मंशा क्या है? उसे गम्भीरता से समझने की जरूरत है। दिल्ली के शाहीनबाग में चल रहे धरने पर रोजाना जो लाखों रूपयों की रकम खर्च की जा रही है, उस पर खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह पैसा विदेशों से भारत में अस्थिरता पैदा करने के नाम पर पी.एफ.आई. द्वारा जुटाया जा रहा है। यह वही पी.एफ.आई. है जो भारत को इस्लामी राज्य बनाना चाहता है।

यह बात भी अब जन–जन तक उजागर हो चुकी है कि बांग्लोदश के हिन्दू हमेशा से कट्टरपंथी मुस्लिम जमातों के निशाने पर रहे हैं। आये दिन हिन्दुओं की वहाँ हत्या कर दी जाती है, उनके घरों, दुकानों पर बलात् कब्जे हो रहे हैं।

तीनों मुस्लिम इस्लामिक देशों में हिन्दुओं पर हो रहे जुल्मों को नजरअंदाज करते हुये भारत के विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति कर मुल्ला–मौलवियों, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं जैसे अपराधी श्रेणी के मुसलमानों को नागरिकता क्यों दिलाना चाहते हैं? घुसपैठियों से इनकी हमदर्दी देश को खतरे में डालने वाली है। वहीं कांग्रेस गांधी जी के आदर्शों को दर–किनार कर नफरत के बीज बो रही है। विरोध के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को शह दे रही है।

प्रवर्तन निदेशालय(ई.डी.) ने मनीलाड्रिंग मामले में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े गैर सरकारी संगठनों के 73 बैंक खातों की जाँच के बाद गृहमंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि इन खातों में 120 करोड़ जमा कराये गये हैं।

ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्मादी इस्लाम को विस्तार देने के काम में जुटा मुस्लिम संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) का कार्यालय इसी शाहीनबाग क्षेत्र में है। यह सिमी का बदला हुआ रूप है। मुस्लिम कट्टरता का यह विचार मस्जिद के आहातों से लेकर विश्वविद्यालयों और मीडिया तक में जड़ें जमाने में सफल रहा है। अब यह हिंसक उन्माद तिरंगे का नकाब लगाकर भ्रमित करने लगा है, जिसके पीछे इसकी चालबाजी और विदेशी मदद छिपायी जा रही है।

अब देश तोड़ने की मुहीम की कलई परत–दर–परत खुलती चली जा रही है। प्रगतिशीलता की आड़ में मीडिया देशघाती मँसूबा बाँधने वाले शरजील इमाम को मंच पर लेखक/पत्रकार के तौर पर प्रतिष्ठा देता है और गिरफ्तारी के बाद केवल 'छात्र' के बतौर उल्लेख करता है। मासूम बच्चों की मौत के मामले में दागी डाक्टर, वकील, सर्वोच्च न्यायालय को न मानने वाली मुस्लिम छात्रा ये सब उजागर हो रहे किरदार हैं। शाहीनबाग में दिये जा रहे भड़काऊ भाषण षड़यंत्रकारियों के लिये देश में सशस्त्र विद्रोह का रास्ता साफ करने की मात्र कवायत है, जो उचित अवसर की तलाश में है।

नागरिकता कानून के नाम पर विरोध भारत में और सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शनों का ज्वार खाड़ी देशों में, इस समानता को क्या समझा जाय? भारत में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश के तहत क्यों नहीं देखा जाना चाहिये? क्या कुछ लोग भारत में सीरिया जैसी तबाही रचने का ताना–बाना बुन रहे हैं? ये भारत को अंदर से कमजोर बनाने की साजिश है।

एक महीने से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। भारत में 'जिन्ना वाली आजादी' जैसे देश विरोधी नारों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये। यह नागरिक संशोधन कानून के विरोध के पीछे की गहरी साजिश का संकेत है। शरजील शमीम द्वारा पूर्वोत्तर को देश के शेष हिस्सों से काटने के लिये उकसाया जाना तथा फैजुल हसन का वह बयान कि ''हम उस समुदाय से हैं, जो अगर चाहें तो किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं।'' ये बयान मात्र देश का सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने भर की कोशिश नहीं है, इन बयानों के माध्यम से जो आग उगली जा रही है, उससे कुछ और गम्भीर तात्पर्य निकलते हैं। पश्चिम मीडिया हमेशा की तरह षड़यंत्रकारियों के कृत्यों को जायज ठहराता रहा है।

पहले ज़नाक्रोश भड़काया जाता है, फिर भ्रम फैलाकर आक्रोश को उबलने लायक बनाया जाता है फिर इसी जनाक्रोश को सशस्त्र विद्रोह में तब्दील किया जाता है। इसीलिये ये तमाम देशघाती तत्व एकत्रित होकर अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने जुट गये हैं।

भारत विश्वभर में एक

शेष भाग पृष्ठ क्र.4 पर

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध
यह भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश तो नहीं है? - डॉ. किशन कछवाहा

काँग्रेस सहित विपक्ष (सी.ए.ए.) नागरिकता कानून को लेकर राष्ट्रधर्म की अनदेखी कर रहा है। साथ ही मुस्लिम वोट बैंक की लालच में उन्हें गुमराह भी कर रहा है। भारत पाक के दुर्भाग्यपूर्ण बँटवारे के बाद महात्मा गाँधी ने स्वयं कहा था कि अगर कभी भविष्य में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ना का शिकार बनाया जाता है तो यह भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे प्रताड़ित होने वाले नागरिकों को शरण देकर नागरिकता प्रदान करे। काँग्रेस गत 70 वर्षों से जुल्म और अत्याचार सह रहे अल्पसंख्यकों (हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसियों आदि) को न्याय दिलाने का काम नहीं कर सकी। अब मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही उस काम को पूरा किया है। अब कौन सी आफत आ गयी है, जो विपक्ष हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है?

भारत हिन्दू राष्ट्र नहीं, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिन्दू बहुत होने के बावजूद। जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल होने के कारण इस्लामिक देश हैं, जहाँ अल्पसंख्यक क्रूर एवं बर्बरता के साथ प्रताड़ित किये जा रहे हैं। यह कानून उन्हें राहत देने के लिये बनाया गया है। इस कानून में भारत में रह रहे मुसलमानों को हानि पहुँचाने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

आश्चर्य तो इस बात का है कि विपक्ष मुसलमानों के बीच तरह–तरह की गलत अफवाहों के फैलाने का दुष्कृत्य कर रहा है, साथ ही देश को आग में झोंकने का भी। काँग्रेस और विपक्ष उन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता क्यों दिलाना चाहता है, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कट्टरतापूर्ण भेदभाव तथा जुल्म कर रहे थे, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता क्यों दिलाना चाहता है, जो सीमा पर सुरक्षाबल की आँख में धूल झोंक कर अवैधानिक तरीके से भारत में घुस आये हैं, और उन रोहिंग्या मुसलमानों का जो असम सहित उत्तरपूर्व के राज्यों में कानून–व्यवस्था बिगाड़ने के लिये जिम्मेदार हैं, इन रोहिंग्या मुसलमानों को तो बांग्लादेश भी खतरनाक मानता है। ये रोहिंग्या तेलंगाना, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में बड़ी संख्या में बस गये हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या है पूरी–पूरी कालोनी बन गयी है। जम्मू–कश्मीर में भी इनकी संख्या कई हजार तक पहुँच चुकी है। जहाँ–जहाँ ये बसे हैं, वहाँ–वहाँ अपराध और तस्करी जैसे दुष्कृत्य बढ़े हैं। सुरक्षा एजेंसियाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें बेहद खतरनाक मानतीं हैं। बताया जाता है कि इस समुदाय के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अपनी पैठ बना चुकी हैं। दिल्ली के कतिपय नेता इन्हें संरक्षण देकर मतदाता पत्र और राशन कार्ड दिलाने में मदद कर रहे हैं। इन तीनों मुस्लिम देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आज भी अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं जिसमें उनके घरों की महिलाओं के अपहरण और नृशंस हत्यायें तक शामिल हैं। ध्यान देने की बात यहां पर यह भी है कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जो एक हिन्दू थे (जोगेन्द्रनाथ मंडल)। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा था। लाखों दलित हिन्दुओं को मार डाला गया या इस्लाम स्वीकार करने बाध्य कर दिया गया।

प्रश्न तो यह भी उठता है कि क्या काँग्रेस भारत पाक विभाजन को गलत मानती है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दिलाकर सत्ता की वापसी के लिये उनका सीढ़ी के रूप में उपयोग करना चाहती है? मुस्लिम लीग और उसके इधर–उधर घुस गये कट्टर मुस्लिम नेता क्या इन्हें नागरिकता दिलाकर भारत को पाकिस्तान बनाने की अपनी दबी हुयी मंशा को पूरा करना चाहते हैं?

सोनिया गांधी की कांग्रेस का पूरा मंतव्य इस बात पर केन्द्रित है कि 'भारत के लिये हिन्दुत्व एक अभिशाप है।' इसलिये जब कांग्रेस के लोग जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 'ला इल्लाह इल्लल्लाह' के नारे लगाते हुये आजादी–आजदी चिल्लाते हैं। तब तब राहुल गांधी 'टुकड़े–टुकड़े गेंग' को प्रोत्साहित करने पहुंच जाते हैं। कल की इटली की नागरिक, आज भारत की नागरिक सोनिया गांधी ''भारत को भी पाकिस्तान तो नहीं बनाना चाहती?'' पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता दिलाना तो मात्र दिखावा तो नहीं हो सकता?

पाकिस्तन की धरती हिन्दू–सिख लड़कियों के बलात् इस्लाम में कन्वर्जन की चीखों से कराह रही है। कट्टरपंथी सोच साजिश के तहत अपने इस्लामी एजेन्डे को पूरा करने में लगी है, लेकिन इस क्रूरता और वहशीपन के खिलाफ विपक्ष या मुस्लिम नेताओं की कभी आवाज नहीं उठी। मणिशंकर अय्यर जैसे काँग्रेसी नेता इस्लामी देश में जाकर कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिन्ता भारत के सेकुलरवाद की है। ऐसी भारत विरोधी हरकतें क्या शर्मनाक नहीं है? यह तो एक उदाहरण है। वहां प्रताड़ित हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि इन कांग्रेस नेताओं को नजर क्यों नहीं आते? उनकी पीड़ा, उनका प्रताड़ित होते रहना– इन पर चुप्पी साधने का तात्पर्य क्या हो सकता है? तीन दशक पहले कश्मीर में भी तो हिन्दुओं के खिलाफ निर्दयता दिखलाई गयी थी। पाँच लाख कश्मीरी हिन्दुओं को 'कश्मीर छोड़ो' के साथ बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। तब भी इन नेताओं के मुँह सिले रहे। आज इन्हें भारत की सेकुलेरिटी खतरे में दिख रही है। सन् 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या, उनके परिवारों की महिलाओं के साथ बलात्कार, घरों, दुकानों, फेक्ट्रियों को आग लगा देने जैसी घटनायें आज भी रोंगटे खड़ा कर देती हैं लेकिन अफसोस है कि तीन दशक बाद भी कोई बुद्धिजीवी, पत्रकार विपक्ष के नेता इस मुद्दे को उठाना मुनासिब नहीं समझते? क्यों? पड़ोसी इस्लामी देशों के हिन्दुओं को काफिर मानने वाले जिहादियों के अत्याचार से बचाने बनाये गये नागरिकता संशोधन से उन्हें क्यों आपत्ति है? ऐसे नेता धरने पर बैठाई गयी मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के बीच पहुंचकर किस प्रकार की और किस उद्देश्य से चिंगारी को हवा देने के लिये धन और बाहुबल का उपयोग कर रहे हैं?

सन् 1946 में कोलकाता में हिन्दुओं के विरूद्ध हुआ 'डायरेक्ट एक्शन प्लान' क्या था? इसमें भी चार दिन में दस हजार से अधिक हिन्दुओं की हत्या कर दी गयी थी। इसमें भी 'दीनदीन' अल्ला हो अकबर तथा 'लड़के रहेंगे हिन्दुस्तान' के नारे लग रहे थे। हत्या, लूटपाट, आगजनी, हिन्दू महिलाओं का अपहरण बलात्कार का दौर बेरोकटोक चलता रहा। 15 हजार लोग गम्भीर रूप से घायल हुये थे। एक लाख लोग बेघरबार हुये थे।

सन् 1947 में विभाजन की त्रासदी के समय जिस प्रकार की क्रूरता और बर्बरता हुयी, उसने हिटलर की फौज की कार्यवाही को भी शमिन्दा कर दिया। 13 लाख लोग मारे गये। डेढ़ करोड़ लोग विस्थापित हुये। साढ़े बारह लाख शरणार्थी भारत आये। एक लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये था धार्मिक आधार पर हुये भारत–पाक विभाजन का दुःखद परिणाम। जब 19 जनवरी 1990 को पांच लाख कश्मीरी पंडितों को जबरन निकाला गया। ये कश्मीर के जिहादी मुसलमानों द्वारा भारत के ही नागरिकों के साथ किया गया। क्रूरतम प्रहार था।

सन् 1947 में आजादी मिलने के समय भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन झेला था। इन तमाम दुःखदायी क्षणों को दिल में सहेजकर रखने की जरूरत है ताकि अब और त्रासदायक क्षणों का सामना न करना पड़े।

सचेत रहना है। वर्षों से

शेष भाग पृष्ठ क्र.4 पर

पाक तिलमिलाया हुआ है

भारत द्वारा जम्मू–कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर देने के निर्णय से पाकिस्तान की तिलमिलाहट और बैचेनी देखने लायक है। उसकी छटपटाहट की पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रहा है। यद्यपि उसने दो देशों एवं सरकारों के बीच कायम रहने वाले सामान्य शिष्टाचार को तो ताक पर रख ही दिया है, अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमले कर अपनी भड़ास निकाल रहा है। इस कारण उसकी ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भद्द पिट रही है। यह व्यवहार अशिष्टता की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान की बढ़ती बौखलाहट विश्व समुदाय के समक्ष बड़ी गम्भीरता से देखी जा रही है।

सन् 1947 को हुये भारत–पाक बंटवारे के समय से ही पाकिस्तानी नेताओं की लालसा जम्मू–कश्मीर से जुड़ी रही है। उसके द्वारा यह आसक्ति की श्रेणी की मानसिकता है, जो वर्षों से पालित–पोषित रही है। अब उस मानसिकता को भारत के द्वारा अभी हाल में उठाये गये कदम से मार्मिक पीड़ा पहुंची है। पाकिस्तान द्वारा उस कदम के खिलाफ कश्मीर की यथास्थिति में लाये जाने के लिये वह हर प्रकार का जोखिम उठाने तैयार दिख रहा है। यद्यपि पाकिस्तानी शासक अब तक अनेक बार अपनी ताकत को आजमाने के बाद असफल ही सिद्ध हुये हैं। लड़ाईयों भी लड़ी गयी और उसमें भी असफलतायें हाथ लगीं। सन् 1990 से उसने सीधी लड़ाई न लड़ते हुये अप्रत्यक्ष युद्ध का एक तरीका आतंकवाद का भी परोसा लेकिन भारत की ताकत के सामने लाचारी ही सामने आयी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उसके द्वारा गुहार लगाई गयी। वहाँ भी कोई चर्चा तक के लिये तैयार नहीं हुआ। यह पाकिस्तान के लिये सदमा जैसा था। पाकिस्तान के शासक प्रारम्भ से ही यह आशा पाले हुये थे कि एक दिन जम्मू–कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जायेगा। इसके लिये वे सब प्रकार के जायज–नाजायज उपायों के माध्यम से चरणबद्ध प्रयास करते रहे हैं। पाकिस्तानी जनता को भी ऐसा करने का वादा कर भरमाये हुये थे। अब भारत के इस 5 अगस्त वाले कदम से उनका सपना चकनाचूर होता दिखने लगा है।

पाकिस्तान में हर वर्ष पाँच फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन वहाँ सार्वजनिक अवकाश रहता है। भारत के खिलाफ जहर उगलने को खुला अवसर मिलता है। सम्भव है इस आगामी 5 फरवरी को और भी अधिक भड़ास निकाली जाय। दुष्प्रचार के मामले में पाकिस्तान के नेताओं ने अब तक कोई कोर–कसर बाकी भी नहीं रखी। भारत के खिलाफ विष–वमन जारी रखना उनकी मजबूरी भी है लेकिन असलप्रश्न यह है कि अब भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान करेगा क्या?

भारत सरकार कहती आ रही है कि वह अपनी एक इंच जमीन के साथ भी समझौता नहीं करेगा। जम्मू–कश्मीर के उस हिस्से के बारे में भी जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, के सम्बन्ध में भी पूर्व में भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उस भूमि को खाली करने के बारे में भी भारत के नेता पाकिस्तान को चेतावनी दे भी चुके हैं।

अंतर्राष्ट्रीयता तभी पनप सकती है, जब राष्ट्रीयता का सुदृढ़ आधार हो। –डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

विस्तानवाद का इलाज खोजिये – हितेश शंकर

जम्मू–कश्मीर–लद्दाख की बदली स्थिति, माइनो–वाड्रा– गांधी परिवार की सुरक्षा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय फीस वृद्धि जैसे मुद्दे अहम हैं, किन्तु संसद के गत सत्र में इन मुद्दों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण बात दब –सी गई।

अरूणाचल की ओर फिर से बढ़ते चीनी दखल–दबदबे की ओर तापिर गाओ ने ध्यान दिलाया, जो अरूणाचल पूर्व सीट से सांसद हैं। 19 नवम्बर को उन्होंने लोकसभा में कहा कि चीन अरूणाचल प्रदेश में भातीय सीमा में 50–60 किलोमीटर तक घुसपैठ कर चुका है और यदि उसे नहीं रोका गया तो राज्य में दूसरा डोकलाम बन जाएगा।

दक्षिण तथा पश्चिम में लम्बी तटरेखा और उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के होने पर भी भारत में जैसी शांत स्थितियाँ होनी चाहिए थीं वे ऐतिहासिक कारणों से हो नहीं सकीं। पिछले सत्तर वर्ष में भारत के पाकिस्तान से चार और चीन से एक युद्ध इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि पड़ोस में उन्मादी–उपद्रवी पाकिस्तान और विस्तारवादी चीन इसके दो अलग–अलग कारक थे। सोवियत संघ के बिखराव के बाद से भारत ने उत्तरी क्षेत्र में शांत मजबूत पड़ोस की आवश्यकता को लगातार अनुभव किया है। यही वह क्षेत्र जहां से भारत को आतंकित, अस्थिर करने वाले आतंकी तंत्र और नकली मुद्रा की सेंधमारी होती रही।

एशिया से वैश्विक सहयोग, समन्वय और समृद्धि के रास्ते खुल सकते थे, किन्तु चीन की ओर से संसाधानों पर कब्जे की होड़ और बाजारों को पंजे में रखने की सीपैक जैसी योजनाएं अब कई देशों को अखर रही हैं। दरअसल, चीन ने ताबड़तोड़ उत्पादन के बूते बाजारवाद की जो बिसात बिछाई है उसके नीचे साम्यवाद तो बहुत पहले दफनाया जा चुका है। अब तो किसी भी कीमत पर बाजार की चक्की चलाते रहने वाला 'जिन्न' है जो उसकी छाती पर चढ़ा बैठा है। विस्तारवाद का अघोषित लक्ष्य लेकर चलते हुए, आर्थिक सौदेबाजी से भू–राजनैतिक स्थितियों का पलड़ा अपने पक्ष में झुकाना ही आज चीन की विदेश–रक्षा और अर्थनीति का मूल है।

जम्मू–कश्मीर–लद्दाख की बदली स्थिति से पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठी, यह पहली और जगजाहिर बात है। दूसरी बात चीन की लद्दाख के कुछ हिस्से को अपना बताते हुए की गई आपत्ति है। तीसरी आपत्ति आश्चर्यजनक रूप से नेपाल की ओर से भारत के उस कालापानी क्षेत्र पर आई है, जिस पर नेपाल के किसी शासक की ओर से कभी कोई सवाल तक नहीं किया गया।

इन तीन बिन्दुओं के साथ जुड़ता चौथा आयाम खुफिया एजेंसियों से निकली उन खबरों में है जिनके अनुसार उत्तराखण्ड के लिपुलेख दर्रे के पास चीन सैन्य अड्डे मजबूत कर रहा है। नेपाल, तिब्बत और भारत के बीच पड़ने वाली इस जगह हैलिपैड बनाने के अलावा 20 विमानों के खड़े होने तथा रखरखाव की जगह बनाई जा रही है। लम्बे समय से पाकिस्तान को भारतीय 'अघोषित शत्रु' के तौर पर ही देखते हैं। यदि कहा जाए कि मीडिया रिपोर्टिंग और बॉलीवुड की फिल्मों ने भी इस दृष्टिकोण को मजबूती दी तो गलत नहीं होगा। परंतु भू–राजनीतिक गतिविधियों से उजागर संकेत बताते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मोहरा है, ड्रैगन का पिट्ठू! भारत की असली चिंता पर्दे के पीछे छिपा चीन होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि जब–जब भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षामंत्री अरूणाचल की यात्रा पर गए चीन ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सार्वजनिक तौर पर इन दौरों का विरोध किया।

तो भारत क्या करे! वक्त आ गया जब सीमाओं और चिंताओं को लेकर भारत को सिर्फ मुस्तैद नहीं बल्कि और ज्यादा मुखर भी होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय रूख की सरकार के अलावा मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन एक बात का ध्यान तो रखना होगा, भारतीय समाज विभाजक मुद्दे लपकने वाले कथित बुद्धिजीवी भला क्यों चाहिए? ऐसे समझदारों का आप क्या करेंगे जिनके चेहरे जेएनयू से उठते 'आजादी' के नारों पर खिल उठते हैं मगर थ्येनआनमन चौक छात्र नरसंहार या हांगकांग में आजादी के लिए प्रताड़ित होते छात्रों के जिक्र से जिनकी 'अक्लदाढ़' दुखने लगती है!

इतिहास से सबक लेकर चीजें ठीक की जाती हैं। 'हिन्दी–चीनी, भाई–भाई' की नीति ने भारत को और चीन के साथ पंचशील समझौते ने तिब्बत को किस तरह नुकसान पहुंचाया यह दुनिया ने देखा है। तिब्बत की स्वायत्तता की अलख करीब–करीब भारत की आजादी जितनी ही पुरानी है। सुदूर फिलिस्तीन पर रोने वाले भारतीय बुद्धिजीवी भला कब उस तिब्बती क्षेत्र की चिंता, वहां की संस्कृति और मानवाधिकारों की बात करेंगे, जिसकी सीमा भारत से लगती है। यह समय उन नई संतुलित आवाजों को साधने–उभारने का है जिनके लिए एक भारत, श्रेष्ठ भारत का नारा मायने रखता है और जो किसी 'इज्म' के मारे नहीं है।

यदि रखिए, सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन राष्ट्रीय सरोकार के स्वरों के बिना सरकारें कुछ नहीं कर सकतीं।

शेष भाग पृष्ठ क्र.1 का

मात्र ऐसा देश है, जहाँ मुसलमानों के 72 फिरके अमन–चैन से रहते हैं। बार–बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि सी.ए.ए. पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के जान–माल धर्म की हिफाजत के लिये बना है। इससे भारत में रह रहे किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जायेगी। इसके बावजूद मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, उनका मकसद समाज में हिंसा करवाना है। यह आन्दोलन उन हाथों के जरिये संचालित किया जा रहा है, जो भारत को खोखला कर देना चाहते हैं। इनमें वे भी शामिल हैं, जिन्होंने मजहब के नाम पर मातृभूमि के टुकड़े–टुकड़े करने की जिद पाल रखी है। भारत में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आग भड़काने के लिये पाकिस्तानी सेना का प्रचार तंत्र भी पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है।

भारतीय जाँच और सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग करने वाली एक साईबर सुरक्षा फर्म की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता कानून के विरोध को भड़काने के लिये एक हजार से अधिक पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल काम कर रहे हैं।

यह स्मरण रखना चाहिये कि शाहीनबाग जैसे तौर–तरीके ही भारत–पाक बंटवारे की नींव बने थे। सी.ए.ए. के दिशा हीन विरोध और एन.आर.सी. तथा पी. एन.आर. का हौआ खड़ा कर मुस्लिम समाज में कट्टरपंथी नेतृत्व को पनपने का मौका देकर विपक्ष ने जो गलती की है उसके दुष्परिणाम उसे भविष्य में भुगतना ही होंगे। शाहीनबाग जैसे आन्दोलनों का विपक्ष को विरोध करना चाहिये था।

भारत का एक पूर्ण इस्लामिक राज्य में तब्दील करने का मंसूबा कोई नया नही है। सभी मुगल शासकों/आक्राताओं ने ऐसा प्रयास किया भी/पी.एफ.आई. याने मुस्लिमों की संस्था पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी हर कदम इसी मंसूबे को पूरा करने के लिये उठता है। पी.एफ.आई. कई मुस्लिम संगठनों का समूह है इसकी उन तमाम मुद्दों पर सक्रियता देखी जाती है, जो अखबारों की सुर्खियाँ बनते हैं और जिनमें जातिगत विद्वेष या मजहबी उन्माद बढ़ाने की संभावना नजर आती है।

शाहीनबाग में सी.ए.ए. का विरोध लेकिन नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के समर्थन में। असम को देश से अलग करने की बात की जा रही है। क्या इस प्रकार के रवैये और तकरीरों को देश विरोधी नहीं माना जाना चाहिये? यह तो आजादी के पहले हुये मुस्लिमों के खिलाफत आन्दोलन जैसी मानसिकता थी। आप पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ आगे बढ़कर जामिया क्षेत्र में पहुंची और वहाँ प्रदर्शन हिंसक हो गया पत्थरबाजी, आगजनी, पेट्रोलबम फेंका जाना और फिर पुलिस पर भी हमला। इन हिंसक घटनाओं में कट्टरपंथी मुसलमानों के अलावा बड़ी संख्या में बांग्लादेश तथा पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। उन्हीं आपराधिक तत्वों को बचाने के लिये शाहीनबाग में महिलाओं और बच्चों को आगे कर धरना दिया जा रहा है।

शेष भाग पृष्ठ क्र.2 का

सत्ता पर काबिज रहे तथा कथित सेकुलरों ने 'भारतभाव' को सदैव अपमानित करने का कुकृत्य किया है। भारत के प्रति आस्था एवं निष्ठा का भाव रखने वाले समाज को विघटित करने के कुचक्र रचे हैं। आज भी उनके ऐसे प्रयास जारी है। समूची शिक्षा प्रणाली को तहसनहस कर दिया गया है। इतिहास को उलट–पलट कर इस देश के महापुरूषों की उपेक्षा करते हुये विधर्मी आक्रमणकारियों–आततायियों का महिमामंडन किया है। अब ये तत्व ऐसे कृत्यों में संलग्न रहकर सफल न हो पाये– इसकी चिन्ता करना है।

हिन्दू बहुल होने के कारण ही भारत पंथ निरपेक्ष (सेकुलर) बना रह सका है। यदि मुसलमानों की आबादी अधिक होती तो क्या यह राष्ट्र पंथ निरपेक्ष(सेकुलर) रह पाता? इस तथ्य को गम्भीरता से समझ लेने की जरूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा इस्लामी राष्ट्र बन गया होता?

भारत में हिन्दू जनता के साथ छल और अन्याय कांग्रेस पर अत्यधिक भरोसा करने के कारण होता ही रहा है। नेहरूवादियों, नकली गाँधियों और साम्यवादियों के इस षड़यंत्र को हिन्दू जनता चुपचाप सहन भी करती रही है और अब भी सहन कर रही है। भला हो बहुसंख्यक हिन्दुओं कि उन्होंने अपने विशेषाधिकारों के लिये अब तक माँग नहीं उठायी है। यदि वे माँग उठाने लगेंगे तक क्या हश्र होगा? इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक जो भी सुविधाऐं और सहूलियतें दी गयी हैं, वे केवल अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाती रही हैं 'अल्पसंख्यक' शब्द की भ्रामक अवधारणा से बहुसंसख्यक हिन्दुओं के साथ लगातार छल और अन्याय होता रहा है, जिसे चुपचाप सहन किया गया है।

विपक्ष : अराजकता को बढ़ावा

देश की जनता देख रही है, और समझ भी रही है कि विपक्षी दल विरोध के नाम पर संविधान की मर्यादा को तार–तार कर रहे हैं लेकिन वे इस अपने दुष्कृत्य को यह कह कर ढँकने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ''संविधान की रक्षा कर रहे हैं। गत दिनों केरल विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ जिस प्रकार का मर्यादा विहीन व्यवहार किया, उसे संसदीय अभद्रता कहना ही उचित होगा।''

कॉंग्रेस भी वामदलों के साथ खड़े होकर केरल में और प. बंगाल में भी प्रस्ताव पारित करने सहयोग ही किया। सी.ए.ए. का विरोध करने में सबसे अधिक सक्रियता कॉंग्रेस वामदल और तृणमूल कॉंग्रेस ने ही दिखाई। कारण स्पष्ट भी है कि इन्हीं दलों का जनाधार तेजी से खिसकता चला जा रहा है।

जन–जन में यह चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि विपक्ष जहां एक ओर लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, वहीं वह मर्यादा हीन व्यवहार करते हुये संवैधानिक मर्यादा को भी तार–तार करने से नहीं चूक रहा।

कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दल शायद इस मुगालते में है कि वे ऐसे अराजकता पूर्ण माहौल तैयार कर अपने राजनैतिक मंसूबे को साध सकते हैं। वेवजह धरना प्रदर्शन, बंद व आंदोलन कर देश को अस्थिर करने का उनका प्रयास इनको कहीं का नहीं रखेगा। देश ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं करेगा।

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

— सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com